



दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

RNI NO :- CHHIN/2018/76480

Email :- nyaysakshi@gmail.com

रायगढ़, बुधवार 03 अप्रैल 2019

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए

वर्ष-01, अंक-182

महत्वपूर्ण एवं खास

असम में अधिकारीक बलों की 120 से अधिक कंपनियां तैनात

गुवाहाटी (आरएनएस)। असम में चुनावी इट्यूटी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्थसैनिक बलों की 120 से अधिक कंपनियां तैनात की गई हैं। असम के पुलिस महानिदेशक कुलाधर सैकिया ने सोमवार को यथां पुलिस मुख्यालय में संवादाताओं को संबोधित करते हुए कहा, राज्य में चुनाव के लिए अतिरिक्त 33 कंपनियों को बाहर से भेजा गया है। और ये सभी कंपनियां चुनाव से पहली की गतिविधियों में जग्य सुरक्षा बलों के साथ लगाई गई हैं। हमारे पास पहले ही केन्द्रीय अधिकारीक बलों की 90 कंपनियां हैं।

बिना कोर्ट की परमिशन के बाद विदेश जा नहीं सकेंगे

मनी लाइंग में भिली अधिक जमानत

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा रंबंड वाड़ा को आज दिल्ली की एक अदालत ने मनी लाइंग मामले में अधिक जमानत दी दी। वाड़ा को 5 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। वाड़ा के साथ मनोज अरोड़ा को भी अधिक जमानत मिली है। जमानत मिलना जहां वाड़ा के लिए राहत की खबर है वहां स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने जमानत पर कुछ शर्तें लगाते हुए कहा कि बिना कोर्ट की अनुमति के अंतर्गत वाड़ा देश छोड़ नहीं सकते। साथ ही इन दोनों को जब भी कोर्ट में बुलाया जाए हैं कोर्ट आना पड़ेगा। सबूतों के साथ छेड़छाड़ सहन नहीं की जाएगी। कोर्ट ने दोनों को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश भी दिया है।

याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

हार्दिक पटेल को फिर लगा झटका

नई दिल्ली (आरएनएस)। गुजरात के पारिदार नेता हार्दिक पटेल को मेहसाना दंगा मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। हार्दिक ने इस मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इकान कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस पर तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 4 अप्रैल की तारीख तय की है।

भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान के 3 जवान ढेर

जम्मू (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से सटे गांवों में पाकिस्तान की ओर से मंगलवार को भी संघर्ष विराम के उल्लंघन कर गोलीबारी की गई। भारतीय सेना ने भी मुंतोड जवाब देते हुए पाक के तीन सैनिकों को मार गिराया है।

मेहसाना दंगा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दिया हार्दिक पटेल को बड़ा झटका, जल्द सुनवाई की याचिका खारिज की

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिया हार्दिक पटेल को बड़ा झटका, चुनाव लड़ने के कोर्ट के फैसले पर तत्काल सुनवाई से मना किया। 4 अप्रैल को होंगी सुनवाई, और उसी दिन ही 2015 के हिंसा भड़काने के मामले में याचिका दी थी जिससे कि लोकसभा चुनाव लड़ सकें।

प्लास्टिक बैग बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर

नई दिल्ली। दिल्ली के समयावधी बादली इलाके में एक प्लास्टिक बैग बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर।

पाकिस्तान काठमांडू में नेशनल डिफेंस कॉलेज बनाएगा

चीन की तर्ज पर पाकिस्तान नेपाल से नजदीकी बड़ाने की कोशिशों में लगा हुआ है। जिससे वो नेपाल में भारत के प्रभाव को कम कर सके। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान काठमांडू में नेशनल डिफेंस कॉलेज बनाना चाहता है, जिससे वह नेपाल की सेना में अपनी पैठ मजबूत कर सके।

कांग्रेस के घोषणापत्र में किसानों के लिए अलग बजट

अति गरीब परिवार को वर्ष में 72 हजार, घोषणा पत्र का शीर्षक-हम निभायेंगे



लक्ष्य होगा कि कोई भी भारतीय परिवार पीछे न छू जाये।

कांग्रेस ने घोषणा पत्र में न्याय यानी न्यूनतम आय योजना, छोटे उद्यमियों को बढ़ाना और टैक्स में राहत सिर्फ वादे किये गए हैं। घोषणा पत्र में सेना का आधिकारीक राज्य राष्ट्र फैले हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र का शीर्षक है-हम निभायेंगे।

कांग्रेस के घोषणा पत्र में न्याय

यानी न्यूनतम आय योजना, छोटे

उद्यमियों को बढ़ाना और टैक्स में

राहत सिर्फ वादे किये गए हैं।

घोषणा पत्र में कहा है कि वर्ष

2030 तक गरीबी का नामेनिशन

मिटाने के लिए कांग्रेस न्यूनतम आय

योजना की सुरुआत करेंगी, भारत की

20 प्रतिशत सबसे गरीब आबादी को

हर साल बहतर हजार रुपये

(72,000) दिये जायेंगे। कांग्रेस का

क्षेत्रीय स्तर पर नये संस्थानों (छोटे बैंकों) की स्थापना को प्रोत्साहित करेंगी, ताकि एम.एस.एम.ई. को उत्थन उपलब्ध करवाया जा सके। घोषणा पत्र में लिखा गया है- कांग्रेस शहरीदों के परिवारों को मुआवजे की नीति तैयार करने और लागू करने का वचन देती है। इस नवी नीति में पूर्ण वेतन और भर्ते शामिल होंगे, बच्चों की शिक्षा के लिए धन तथा शहीद परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी और उत्पुक्त मौद्रिक मुआवजा शामिल होंगा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में एलजीबीटी अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, महिला सशक्तिकरण का जिक्र किया है। कांग्रेस ने वादा किया है कि अलगा से किसान बजट आएगा।

कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि एलजीबीटी के लिए धन तथा शहीद परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी और लागू करने का वचन देती है। इस नवी नीति में पूर्ण वेतन और भर्ते शामिल होंगे।

कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम

17वीं लोकसभा के पहले सत्र में और

साथ ही राज्यसभा में, उनमादी भीड़ द्वारा, आगजनी और हत्या जैसे नफरत

भरे अपराधों की रोकथाम और दंडित करने के लिये नया कानून पारित करायेंगे। इस कानून में पीड़ितों को मुआवजा देने और लापरवाही के लिए पुलिस और रोजगार पैदा करते हुए।

कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम

जिसके लिए धन तथा शहीद परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी और लागू करने का वचन देती है। इस नवी नीति में पूर्ण वेतन और भर्ते शामिल होंगे।

कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम

जिसके लिए धन तथा शहीद परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी और लागू करने का वचन देती है। इस नवी नीति में पूर्ण वेतन और भर्ते शामिल होंगे।

कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम

जिसके लिए धन तथा शहीद परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी और लागू करने का वचन देती है। इस नवी नीति में पूर्ण वेतन और भर्ते शामिल होंगे।

कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम

जिसके लिए धन तथा शहीद परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी और लागू करने का वचन देती है। इस नवी नीति में पूर्ण वेतन और भर्ते शामिल होंगे।

कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम

जिसके लिए धन तथा शहीद परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी और लागू करने का वचन देती है। इस नवी नीति में पूर्ण वेतन और भर्ते शामिल होंगे।

कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम

जिसके लिए धन तथा शहीद परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी और लागू करने का वचन देती है। इस नवी नीति में पूर्ण वेतन और भर्ते शामिल होंगे।

कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम

जिसके लिए धन तथा शहीद परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी और लागू करने का वचन देती है। इस नवी नीति में पूर्ण वेतन और भर्ते शामिल होंगे।

कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम

जिसके लिए धन तथा शहीद परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी और लागू करने का वचन देती है। इस नवी नीति में पूर्ण वेतन और भर्ते शामिल होंगे।

कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम

<div data-bbox="